भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5327

उत्तर देने की तारीख 05 अप्रैल, 2023

दूरसंचार नेटवर्क

5327. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक दूर-संचार कंपनियां आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क और अवसंरचना परियोजनाओं को स्थापित करने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से उक्त परियोजनाओं को शुरू करता है और इनके लिए निधि प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी कंपनियां अपना दायित्व पूरा करने में विफल रही हैं और दूरसंचार विभाग द्वारा इन कंपनियों को क्या परामर्श जारी किए हैं और दूरसंचार विभाग द्वारा जारी परामर्श या चेतावनी पर उन कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दूरसंचार कंपनियों द्वारा देश के आकांक्षी जिलों में अपनी परियोजनाओं को समय-सीमा के अनुसार पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) और (ख) किसी क्षेत्र में मोबाइल सेवाएं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा सेवा से वंचित बसे गांवों में मोबाइल कवरेज चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा सरकार ने आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के सेवा से वंचित गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए निम्नलिखित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा वित्तपोषित स्कीमों को मंजूरी दी है:

i. **502 आकांक्षी जिला परियोजना:** 686 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना चार राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आकांक्षी जिलों के 502 सेवा से वंचित गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के सेवा से वंचित अतिरिक्त 27 गांवों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

ii. **7287 आकांक्षी जिला परियोजना:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 7287 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज के प्रावधान के लिए 6,466 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी है।

iii. **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) चरण-II परियोजना:** इस परियोजना के तहत 10 एलडब्ल्यूई राज्यों के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा चिन्हित किए गए 2,542 स्थानों पर 4जी मोबाइल

टावरों को स्थापित करके कवर करने की योजना है जिसकी अनुमानित लागत 2,211.17 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) कानून और व्यवस्था, भूमि आवंटन, वन संबंधी अनुमति आदि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। इस संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों को भी सलाह दी जाती है कि वे परियोजना को जल्द पूरा करने हेतु तेजी से रोल आउट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

*****